



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १५]

बुधवार, जून १७, २०१५/ ज्येष्ठ २७, शके १९३७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास और मत्स्यउद्योग विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित १ जून २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2015.

AN ORDINANCE
TO AMEND THE MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION
ACT, 1981.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९८१ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके
का महा. कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में
५४।

अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग संक्षिप्त नाम तथा करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :-
प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।

सन् १९८१ का
महा. ५४ की
धारा २ में
संशोधन।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् १९८१
का महा.
५४।

२. महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे “ मूल अधिनियम ” कहा गया है) की धारा २ के खंड (एक) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :-

(झ) “ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ” का तात्पर्य, मत्स्य उद्योगों के सहायक आयुक्त से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे क्षेत्र में इस अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रेशन अधिकारी को उसपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन में करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा ;” ।

सन् १९५८
का ४४।

सन् १९८१ का
महा. ५४ की
धारा १३ में
संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (१) में, “ राज्य पत्तन संगठन का मुख्य पत्तन अधिकारी ” शब्दों के स्थान में, “ मत्स्योद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य ” शब्द रखे जायेंगे ।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य के समुद्री किनारों समेत समुद्र में जहाज से मछुवाह के विनियमन के लिये, महाराष्ट्र समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ (सन् १९८१ का महा. ५४) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ड) में, “ अनुज्ञापन अधिकारी ” पद और खण्ड (झ) में “ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ” पद परिभाषित किया गया है। राज्य पत्तन संगठन में अनुज्ञापन अधिकारी, सहायक मछुवाही विकास अधिकारी है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक अधिकारी या सेवक है, अर्थात् महाराष्ट्र समुद्री, बोर्ड किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये प्रमुख पत्तन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। अतः, मछुवाही जहाज के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी और मछुवाही के लिये ऐसे मछुवाही जहाज के उपयोग के लिये अनुज्ञप्ति महाराष्ट्र सरकार के दो विभिन्न विभागों के दो विभिन्न प्राधिकारियों को समनुदेशित की गई थी।

२. देश के समुद्री किनारों में आतंकवादी आशंका की पार्श्वभूमी पर, तटीय सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिये, संपूर्ण देश में अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में एकरूपता रखना आवश्यक है, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि, मछुवाही जहाजों के अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, एकल प्राधिकरण अर्थात् राज्य मत्स्यउद्योग विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने दिनांकित १४ अगस्त २०१४ की अधिसूचना द्वारा, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का ४४) की धारा ४३५घ के प्रयोजन के लिये महाराष्ट्र में पत्तन घोषित किये हैं और धारा ४३५ड के प्रयोजन के लिये भारतीय मछुवाही नौकाओं के रजिस्ट्रार के रूप में मत्स्यउद्योग के सहायक आयुक्त की नियुक्ति भी की है।

तटीय सुरक्षा की सुनिश्चिति और महाराष्ट्र राज्य में मछुवाही जहाजों के अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण में एकरूपता रखने के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी और मछुवाही नौकाओं को अनुज्ञापन देने की शक्ति केवल एक विभाग को अर्थात् मत्स्यउद्योग विभाग को देना इष्टकर समझा गया है, जैसा कि अन्य तटीय राज्यों और संघ क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिये, सरकार, उक्त अधिनियम की धारा २ के खण्ड (झ) में उपबन्धित “ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ” पद की परीभाषा में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

महाराष्ट्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा १३ में यथोचित संशोधन द्वारा, राज्य पत्तन संगठन के मुख्य पत्तन अधिकारी के बजाय मत्स्यउद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार को अपिलिय प्राधिकारी के रूप में सशक्त करना इष्टकर समझती है।

३. क्योंकि राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, समुद्री मछुवाही विनियमन अधिनियम, १९८१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित ३० मई २०१५।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

महेश पाठक,

शासन सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।